

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

12 - 18 APRIL 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Under RBI's proposed new framework, what is the asset size threshold for classifying an NBFC in the Upper Layer?

प्रश्न: RBI के प्रस्तावित नए ढांचे के तहत किसी NBFC को अपर लेयर में वर्गीकृत करने के लिए संपत्ति आकार की सीमा क्या है?

- A) ₹50,000 crore / ₹50,000 करोड़
- B) ₹75,000 crore / ₹75,000 करोड़
- C) ₹1 lakh crore / ₹1 लाख करोड़
- D) ₹1.5 lakh crore / ₹1.5 लाख करोड़
- E) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India has proposed that NBFCs with assets of ₹1 lakh crore or more will be classified as Upper Layer (NBFC-UL).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रस्ताव दिया है कि ₹1 लाख करोड़ या उससे अधिक संपत्ति वाले NBFCs को अपर लेयर (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- This new asset-size based method replaces the earlier parametric scoring system based on size, leverage, and complexity.
- यह नई संपत्ति-आधारित पद्धति पहले की पैरामेट्रिक स्कोरिंग प्रणाली (आकार, लीवरेज और जटिलता पर आधारित) को प्रतिस्थापित करती है।
- The new system makes classification transparent, objective, and non-discretionary.
- यह नई प्रणाली वर्गीकरण को पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और गैर-विवेकाधीन बनाती है।
- The top 50 NBFCs based on total exposure will also be automatically considered for Upper Layer classification.
- कुल एक्सपोजर के आधार पर शीर्ष 50 NBFCs को भी स्वतः अपर लेयर वर्गीकरण के लिए शामिल किया जाएगा।
- Government-owned NBFCs such as PFC, REC, and IRFC will also be included if they meet the threshold.
- PFC, REC और IRFC जैसे सरकारी NBFCs भी इस सीमा को पूरा करने पर शामिल किए

जाएंगे।

- The ₹1 lakh crore threshold will be reviewed every five years under the Scale-Based Regulation (SBR) framework.
- ₹1 लाख करोड़ की सीमा की हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी, जो स्केल-बेस्ड रेगुलेशन (SBR) ढांचे के अंतर्गत आता है।

Static Part :-

- Proposed Threshold — ₹1 lakh crore (asset size)
- Classification — NBFC Upper Layer (NBFC-UL)
- Old Method — Parametric Scoring (Quantitative + Qualitative + Supervisory Judgment)
- New Method — Asset Size Based (Simple & Transparent)
- Auto-inclusion — Top 50 NBFCs by Total Exposure
- Govt NBFCs Included — PFC, REC, IRFC (if threshold met)
- NBFCs in UL (2024-25) — 15 entities
- Review Period — Every 5 Years
- Framework — Scale-Based Regulation (SBR) of NBFCs
- 4 Layers of SBR — Base Layer, Middle Layer, Upper Layer, Top Layer

Ques: According to the Worldline report, by what percentage did UPI QR codes grow in India in 2025?

प्रश्न: वर्ल्डलाइन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में UPI QR कोड कितने प्रतिशत बढ़े?

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 20%
- E) 25%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's digital payments ecosystem is expanding rapidly with UPI QR codes growing by 15% in 2025.
- भारत का डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 2025 में UPI QR कोड 15% बढ़े।
- According to the report released by Worldline, the total number of QR codes reached 731.38 million.
- वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल QR कोड की संख्या 731.38 मिलियन तक पहुंच गई है।
- This reflects widespread merchant adoption across the country.
- यह पूरे देश में व्यापारियों द्वारा व्यापक अपनाने को दर्शाता है।
- Transaction volumes also increased by 33%.
- लेनदेन की मात्रा में भी 33% की वृद्धि हुई।
- It indicates a growing preference for fast, seamless, and cashless payments.
- यह तेज, सहज और नकदरहित भुगतान की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- UPI – Unified Payments Interface
- UPI – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
- Launched by – NPCI (National Payments Corporation of India)
- शुरू किया गया – NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
- Year of Launch – 2016
- लॉन्च वर्ष – 2016
- Regulated by – Reserve Bank of India (RBI)
- विनियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

Ques: Which bank became India's second-largest lender by market capitalization in April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 में कौन सा बैंक मार्केट कैप के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- State Bank of India overtook ICICI Bank to become India's second-largest lender by market capitalization in April 2026.
 - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ICICI बैंक को पीछे छोड़ते हुए अप्रैल 2026 में मार्केट कैप के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया।
 - The bank's market capitalization crossed ₹9 lakh crore.
 - बैंक का मार्केट कैप ₹9 लाख करोड़ से अधिक हो गया।
 - This marks SBI's return to the second position for the first time since August 2019.
 - यह अगस्त 2019 के बाद पहली बार SBI की दूसरे स्थान पर वापसी को दर्शाता है।
 - The growth was driven by strong quarterly earnings and high investor confidence.
 - यह वृद्धि मजबूत तिमाही नतीजों और निवेशकों के उच्च विश्वास के कारण हुई।
 - SBI was founded on 1 July 1955 and is headquartered in Mumbai.
 - SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
-

Ques: What is an Insurance Surety Bond (ISB) recently recognised by the Ministry of Coal as an alternative to Bank Guarantee?

प्रश्न: कोयला मंत्रालय द्वारा बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में मान्यता प्राप्त Insurance Surety Bond (ISB) क्या है?

- A) A loan given by banks / बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

- B) A financial guarantee by an insurance company / बीमा कंपनी द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी
- C) A subsidy provided by the government / सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी
- D) A tax exemption certificate / कर छूट प्रमाणपत्र
- E) A type of insurance claim / बीमा दावा

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Coal has recognised Insurance Surety Bonds (ISBs) as an alternative to Bank Guarantees (BGs) for bid and performance security.
- कोयला मंत्रालय ने बोली सुरक्षा और प्रदर्शन सुरक्षा के लिए Insurance Surety Bond (ISB) को बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में मान्यता दी है।
- This move aligns with amendments made in the General Financial Rules (GFR), 2017 by the Ministry of Finance.
- यह कदम वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप है।
- An Insurance Surety Bond is a financial guarantee provided by an insurance company.
- Insurance Surety Bond एक बीमा कंपनी द्वारा दी गई वित्तीय गारंटी होती है।
- It ensures that a contractor or company will complete a project or obligation.
- यह सुनिश्चित करता है कि कोई ठेकेदार या कंपनी परियोजना या दायित्व को पूरा करेगी।
- If the contractor fails, the insurance company compensates the loss.
- यदि ठेकेदार असफल होता है, तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है।
- Unlike a Bank Guarantee, ISB does not require blocking of funds or collateral by the company.
- बैंक गारंटी के विपरीत, ISB में कंपनी को धन या जमानत ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं होती।
- This improves ease of doing business by reducing financial burden on companies.
- यह कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करके व्यापार सुगमता को बढ़ाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry of Coal – Central Ministry
- कोयला मंत्रालय – केंद्रीय मंत्रालय
- General Financial Rules (GFR) – 2017
- सामान्य वित्तीय नियम (GFR) – 2017
- Bank Guarantee – Issued by banks with collateral requirement
- बैंक गारंटी – बैंकों द्वारा जारी, जमानत आवश्यक
- ISB – Promotes liquidity and reduces capital blockage
- ISB – तरलता बढ़ाता है और पूंजी अवरोध कम करता है

Ques: Which of the following is an AI-enabled platform launched by SEBI to strengthen cybersecurity supervision of regulated entities?

प्रश्न: SEBI द्वारा विनियमित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया AI-सक्षम प्लेटफॉर्म कौन सा है?

- A) SUPCOMS / सुपकॉम्स
- B) e-Adjudication Portal / ई-एडजुडिकेशन पोर्टल
- C) C-SAC (Cyber-Sec Audit Compliance) / C-SAC (साइबर-सेक ऑडिट कम्प्लायंस)
- D) SCORES / स्कोर्स
- E) SMART ODR / स्मार्ट ODR

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- SEBI Chairman launched three IT platforms — SUPCOMS, e-Adjudication Portal and C-SAC — on March 24 to enhance ease of doing business and strengthen cybersecurity oversight.
- SEBI चेयरमैन ने 24 मार्च को तीन IT प्लेटफॉर्म — SUPCOMS, ई-एडजुडिकेशन पोर्टल

और C-SAC – लॉन्च किए, जो व्यापार सुगमता बढ़ाने और साइबर सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए हैं।

- SUPCOMS is a unified communication platform that replaces traditional email-based interactions and ensures centralized access with full audit trail.
- SUPCOMS एक एकीकृत संचार प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक ईमेल आधारित संवाद को बदलता है और पूर्ण ऑडिट ट्रेल के साथ केंद्रीकृत एक्सेस प्रदान करता है।
- The e-Adjudication Portal digitally enables quasi-judicial proceedings, allowing entities to access notices, submit replies and attend hearings online.
- ई-एडजुडिकेशन पोर्टल अर्ध-न्यायिक कार्यवाही को डिजिटल रूप से सक्षम बनाता है, जिससे संस्थाएं नोटिस प्राप्त कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं और ऑनलाइन सुनवाई में भाग ले सकती हैं।
- C-SAC is an AI-enabled platform that strengthens cybersecurity supervision by analysing cyber audit reports and identifying compliance gaps and risk areas.
- C-SAC एक AI-सक्षम प्लेटफॉर्म है जो साइबर ऑडिट रिपोर्टों का विश्लेषण कर अनुपालन अंतराल और जोखिम क्षेत्रों की पहचान करता है।
- It generates actionable insights for data-driven supervisory decisions.
- यह डेटा-संचालित निर्णयों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Regulator – Securities and Exchange Board of India (SEBI)
- नियामक – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
- SEBI Established – April 12, 1988 (Statutory: January 30, 1992)
- स्थापना – 12 अप्रैल 1988 (वैधानिक: 30 जनवरी 1992)
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairman – Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष – तुहिन कान्त पांडेय
- Launch Date – March 24, 2025
- लॉन्च तिथि – 24 मार्च 2025
- Platform 1 – SUPCOMS (Unified Communication)
- प्लेटफॉर्म 1 – SUPCOMS
- Platform 2 – e-Adjudication Portal (Quasi-Judicial)

- प्लेटफॉर्म 2 – ई-एडजुडिकेशन पोर्टल
- Platform 3 – C-SAC (AI-enabled Cybersecurity)
- प्लेटफॉर्म 3 – C-SAC (AI-सक्षम साइबर सुरक्षा)

Ques: Punjab National Bank (PNB) signed an MoU with which platform to provide collateral-free loans to sellers?

प्रश्न: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने विक्रेताओं को बिना जमानत ऋण देने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है?

- A) Government e-Marketplace (GeM) / गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
- B) eNAM / ई-नाम
- C) Amazon India / अमेज़न इंडिया
- D) Flipkart / फ्लिपकार्ट
- E) ONDC / ओएनडीसी

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) has signed an MoU with Government e-Marketplace (GeM).
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ समझौता किया है।
- The partnership aims to enhance financial support for sellers on the platform.
- इस साझेदारी का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- It will provide collateral-free loans, especially to MSMEs and small businesses.
- इसके तहत MSMEs और छोटे व्यवसायों को बिना जमानत ऋण प्रदान किया जाएगा।
- Loans will be offered through the GeM Sahay portal to meet working capital requirements.

- यह ऋण GeM सहाय पोर्टल के माध्यम से कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा।
- The initiative will improve ease of doing business and support digital procurement.
- यह पहल व्यापार सुगमता को बढ़ाएगी और डिजिटल खरीद प्रणाली को मजबूत करेगी।
- Under the MoU, PNB will act as a lending partner
- समझौते के तहत, पीएनबी एक ऋण भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Punjab National Bank Established – 1894
- पंजाब नेशनल बैंक स्थापना – 1894
- Headquarters – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Government e-Marketplace (GeM) – Launched in 2016
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) – 2016 में शुरू
- Purpose – Online procurement of goods and services for government
- उद्देश्य – सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
- Ministry – Ministry of Commerce and Industry
- मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Ques: What GDP growth rate has the Asian Development Bank (ADB) projected for India in FY27 (2026–27)?

प्रश्न: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने FY27 (2026–27) में भारत के लिए कितनी GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है?

- A) 6.5%
- B) 7.6%
- C) 7.3%
- D) 6.6%
- E) 6.9%

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has projected India's GDP growth at 6.9% for FY27 (2026–27) in its Asian Development Outlook (ADO) report.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) रिपोर्ट में FY27 (2026–27) के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान लगाया है।
- This is lower than FY26 growth of 7.6%, indicating a slight moderation.
- यह FY26 के 7.6% की तुलना में कम है, जो हल्की मंदी को दर्शाता है।
- ADB's forecast of 6.9% is higher than the World Bank's estimate of 6.6% and equal to the Reserve Bank of India's forecast of 6.9%.
- ADB का 6.9% का अनुमान विश्व बैंक के 6.6% से अधिक है और भारतीय रिजर्व बैंक के 6.9% के अनुमान के बराबर है।
- India's economy is expected to accelerate to 7.3% in FY28, supported by clean energy investments, power sector reforms and manufacturing competitiveness.
- भारत की अर्थव्यवस्था FY28 में 7.3% तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसे स्वच्छ ऊर्जा निवेश, बिजली क्षेत्र सुधार और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा समर्थन देंगे।
- Key risks include global uncertainty due to the West Asia conflict, high energy prices, and volatile trade and financial conditions.
- प्रमुख जोखिमों में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता, उच्च ऊर्जा कीमतें और अस्थिर व्यापार एवं वित्तीय परिस्थितियां शामिल हैं।
- Inflation is expected to rise to 4.5% in FY27 and moderate to 4% in FY28.
- मुद्रास्फीति FY27 में 4.5% तक बढ़ने और FY28 में 4% तक घटने का अनुमान है।
- Central government capital expenditure is budgeted to increase by 11.5% in FY27, supporting investment-led growth.
- केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय FY27 में 11.5% बढ़ने का अनुमान है, जो निवेश-आधारित विकास को समर्थन देगा।

Static Facts:

- Organisation — Asian Development Bank (ADB)

- Established — 1966
- Headquarters — Manila, Philippines
- President — Masato Kanda
- India GDP Forecast FY27 — 6.9%
- India GDP FY26 — 7.6%
- India GDP Forecast FY28 — 7.3%
- World Bank Forecast FY27 — 6.6%
- RBI Forecast FY27 — 6.9%
- Inflation FY27 — 4.5%
- Inflation FY28 — 4%
- Govt Capex Growth FY27 — 11.5%

Ques: What is the minimum net worth requirement proposed by RBI for entities to set up and operate a TReDS platform under the draft TReDS Directions, 2026?

प्रश्न: RBI द्वारा TReDS Directions, 2026 के तहत प्लेटफॉर्म स्थापित और संचालित करने के लिए न्यूनतम नेट वर्थ कितनी प्रस्तावित की गई है?

- A) ₹10 crore / ₹10 करोड़
- B) ₹15 crore / ₹15 करोड़
- C) ₹20 crore / ₹20 करोड़
- D) ₹25 crore / ₹25 करोड़
- E) ₹50 crore / ₹50 करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) issued draft TReDS Directions, 2026 to consolidate existing guidelines into a unified Master Direction.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने TReDS Directions, 2026 का मसौदा जारी किया, जिसका

उद्देश्य सभी दिशानिर्देशों को एकीकृत करना है।

- Under the draft, entities must have a minimum net worth of ₹25 crore to set up and operate a TReDS platform.
- मसौदे के अनुसार, TReDS प्लेटफॉर्म स्थापित और संचालित करने के लिए न्यूनतम नेट वर्थ ₹25 करोड़ होनी चाहिए।
- Existing authorised TReDS entities have time till March 31, 2027 to meet this requirement.
- मौजूदा अधिकृत TReDS संस्थाओं को 31 मार्च 2027 तक इस आवश्यकता को पूरा करने का समय दिया गया है।
- RBI has proposed removing due diligence requirements for MSMEs to simplify onboarding.
- RBI ने MSMEs के लिए ड्यू डिलिजेंस (सत्यापन) की आवश्यकता हटाने का प्रस्ताव दिया है ताकि शामिल होना आसान हो सके।
- Public comments on the draft have been invited till May 1.
- मसौदे पर 1 मई तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
- TReDS (Trade Receivables Discounting System) is a digital platform connecting sellers (MSMEs), buyers (corporates), and financiers (banks/financial institutions).
- TReDS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विक्रेताओं (MSMEs), खरीदारों (कंपनियों) और फाइनेंसर (बैंक/वित्तीय संस्थान) को जोड़ता है।
- Examples of TReDS platforms include Receivables Exchange of India Ltd, M1xchange, Invoicemart, C2treds, and DTX.
- TReDS प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं RXIL, M1xchange, Invoicemart, C2treds और DTXI

Ques: Which organization has launched the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE)?

प्रश्न: Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है?

- A) RBI / आरबीआई
- B) NITI Aayog / नीति आयोग

- C) NSO / एनएसओ
- D) SEBI / सेबी
- E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Statistics Office has launched the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE).
- National Statistics Office ने Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) शुरू किया है।
- It operates under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
- यह Ministry of Statistics and Programme Implementation के तहत कार्य करता है।
- This is the first-ever annual survey of incorporated services sector enterprises in India.
- यह भारत में संयुक्त सेवा क्षेत्र के उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण है।
- The survey covers all States and Union Territories with FY 2024–25 as the reference period.
- यह सर्वेक्षण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है और इसका संदर्भ वर्ष 2024–25 है।
- It aims to create a comprehensive database of sectors like trade, transport, IT, education and health.
- इसका उद्देश्य व्यापार, परिवहन, IT, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है।
- The survey will support evidence-based policymaking and economic analysis.
- यह सर्वेक्षण साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण में सहायक होगा।
- Data will be collected through a secure web-based portal.
- डेटा सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

Ques: How many strategic pillars and deliverables form the basis of RBI's 'Utkarsh 2029' medium-term strategy framework?

प्रश्न: RBI के 'उत्कर्ष 2029' मध्यम अवधि रणनीति ढांचे का आधार कितने रणनीतिक स्तंभ और डिलिवरेबल हैं?

- A) 5 Pillars and 40 Deliverables / 5 स्तंभ और 40 डिलिवरेबल
- B) 6 Pillars and 49 Deliverables / 6 स्तंभ और 49 डिलिवरेबल
- C) 7 Pillars and 55 Deliverables / 7 स्तंभ और 55 डिलिवरेबल
- D) 6 Pillars and 42 Deliverables / 6 स्तंभ और 42 डिलिवरेबल
- E) 8 Pillars and 49 Deliverables / 8 स्तंभ और 49 डिलिवरेबल

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has unveiled 'Utkarsh 2029', a medium-term strategy framework for the period April 2026 to March 2029.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'उत्कर्ष 2029' का अनावरण किया है, जो अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए एक मध्यम अवधि रणनीति ढांचा है।
- The objective of the framework is to transform RBI into a world-class central bank.
- इस ढांचे का उद्देश्य RBI को एक विश्वस्तरीय केंद्रीय बैंक बनाना है।
- The framework is based on 6 strategic pillars and includes 49 deliverables.
- यह ढांचा 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है और इसमें 49 डिलिवरेबल शामिल हैं।
- The six pillars are — Robust Regulations, Customer Centricity & Inclusive Finance, Competitive Markets, Effective Technology, Future-Ready Organisation and Global India.
- छह स्तंभ हैं — मजबूत नियमन, ग्राहक केंद्रितता एवं समावेशी वित्त, प्रतिस्पर्धी बाजार, प्रभावी प्रौद्योगिकी, भविष्य-तैयार संगठन और ग्लोबल इंडिया।
- Under Project Sa-Mudra, RBI aims to modernise banknote logistics through automation and digital tracking across the currency lifecycle.
- प्रोजेक्ट सा-मुद्रा के तहत RBI मुद्रा जीवनचक्र में स्वचालन और डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से बैंकनोट लॉजिस्टिक्स का आधुनिकीकरण करेगा।

- RBI plans to expand the use of CBDC for efficient cross-border payments and promote bilateral and multilateral CBDC arrangements.
- RBI अधिक कुशल सीमा-पार भुगतान के लिए CBDC के उपयोग का विस्तार करेगा और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा।
- RBI will promote UPI stack globally, enhance international trade settlement in INR, and expand asset tokenisation and AI-based sandboxes.
- RBI वैश्विक स्तर पर UPI स्टैक को बढ़ावा देगा, INR में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को बढ़ाएगा और एसेट टोकनाइजेशन व AI सैंडबॉक्स का विस्तार करेगा।

Static Facts:

- Framework Name — Utkarsh 2029
- Launched By — Reserve Bank of India (RBI)
- RBI Governor — Sanjay Malhotra
- Headquarters — Mumbai
- Period — April 2026 to March 2029
- Total Deliverables — 49
- Number of Pillars — 6
- Previous Framework — Utkarsh 2022 (2019–2022)

Ques: What is the FPI investment limit in Government Securities (G-Secs) for FY 2026–27 as kept unchanged by RBI?

प्रश्न: RBI द्वारा FY 2026–27 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में FPI निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई है?

- A) 4%
- B) 5%
- C) 6%
- D) 8%
- E) 10%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has kept FPI investment limits unchanged for FY 2026–27.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FY 2026–27 के लिए FPI निवेश सीमाओं को यथावत रखा है।
- The limit for Government Securities (G-Secs) remains at 6%.
- सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के लिए सीमा 6% बनी हुई है।
- The limits for State Government Securities (SGSs) and corporate bonds are 2% and 15% respectively.
- राज्य सरकारी प्रतिभूतियों (SGSs) के लिए 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए 15% सीमा निर्धारित है।
- The allocation of incremental G-Sec limits between General and Long-term categories remains at a 50:50 ratio.
- G-Sec की अतिरिक्त सीमा का आवंटन जनरल और लॉन्ग-टर्म श्रेणियों के बीच 50:50 अनुपात में रहेगा।
- The total permissible FPI debt investment is ₹15,51,646 crore for April–September 2026 and ₹16,32,640 crore for October 2026–March 2027.
- कुल अनुमेय FPI ऋण निवेश अप्रैल–सितंबर 2026 के लिए ₹15,51,646 करोड़ और अक्टूबर 2026–मार्च 2027 के लिए ₹16,32,640 करोड़ है।

Ques: What is the key change introduced by IRDAI in its revised cyber security guidelines?

प्रश्न: IRDAI के संशोधित साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में मुख्य बदलाव क्या है?

- A) Reduction in security audits / सुरक्षा ऑडिट में कमी
- B) ISRMC meetings once a year / ISRMC की बैठक साल में एक बार
- C) Quarterly ISRMC meetings & stronger board accountability / तिमाही ISRMC बैठकें और बोर्ड की बढ़ी जिम्मेदारी
- D) Removal of cyber rules / साइबर नियमों को हटाना
- E) No role of board / बोर्ड की कोई भूमिका नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has issued revised cyber security guidelines to strengthen the cybersecurity framework for insurers and intermediaries.
- Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने बीमा कंपनियों और इंटरमीडियरी के लिए संशोधित साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- The Information Security Risk Management Committee (ISRMC) is now required to meet at least once every quarter instead of twice a year earlier.
- अब ISRMC को साल में दो बार के बजाय हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य है।
- This ensures continuous monitoring and stronger cyber risk management.
- इससे निरंतर निगरानी और बेहतर साइबर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- Boards are now required to allocate budgets for cybersecurity.
- बोर्ड को अब साइबर सुरक्षा के लिए बजट आवंटित करना अनिवार्य किया गया है।
- They must review audit findings and ensure closure of gaps within 12 months.
- उन्हें ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करनी होगी और 12 महीनों के भीतर कमियों को दूर करना होगा।
- These changes enhance accountability and strengthen the overall cybersecurity framework in the insurance sector.
- ये बदलाव जवाबदेही बढ़ाते हैं और बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हैं।

Ques: What is the minimum transaction amount above which RBI has proposed a 1-hour delay (lag) for account-to-account digital transfers in its discussion paper?

प्रश्न: RBI के चर्चा पत्र के अनुसार, किस राशि से अधिक के डिजिटल ट्रांसफर पर 1 घंटे की देरी (lag) का प्रस्ताव किया गया है?

- A) ₹5,000
- B) ₹10,000
- C) ₹20,000
- D) ₹50,000
- E) ₹1,00,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) released a discussion paper proposing additional safeguards for digital transactions.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेनदेन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर एक चर्चा पत्र जारी किया।
- One key proposal is a 1-hour delay (lag) for account-to-account transfers above ₹10,000.
- एक प्रमुख प्रस्ताव ₹10,000 से अधिक के ट्रांसफर पर 1 घंटे की देरी लागू करना है।
- This delay will apply at the payer's end before executing the transaction.
- यह देरी भुगतानकर्ता (payer) के स्तर पर लागू होगी।
- Exemptions include merchant payments, recurring payments, and cheque-based payments.
- इसमें व्यापारी भुगतान, आवर्ती भुगतान और चेक भुगतान को छूट दी जाएगी।
- The move aims to curb rising digital frauds, which crossed ₹22,930 crore in 2025.
- इसका उद्देश्य बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना है, जो 2025 में ₹22,930 करोड़ से अधिक हो गई।
- Transactions above ₹10,000 account for 45% of fraud cases (volume) and 98.5% (value).
- ₹10,000 से अधिक के लेनदेन कुल धोखाधड़ी मामलों का 45% (संख्या) और 98.5% (मूल्य) बनाते हैं।
- Another proposal mandates a "trusted person" for transactions above ₹50,000 for senior citizens (70+) and persons with disabilities.
- एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार 70+ आयु वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ₹50,000 से अधिक के लेनदेन पर "विश्वसनीय व्यक्ति" की अनुमति आवश्यक होगी।

- RBI suggested capping annual credits at ₹25 lakh for certain accounts to prevent misuse (mule accounts).
- RBI ने कुछ खातों में वार्षिक क्रेडिट को ₹25 लाख तक सीमित करने का सुझाव दिया है।
- Transfers beyond ₹25 lakh may undergo additional checks before release.
- ₹25 लाख से अधिक के लेनदेन पर अतिरिक्त जांच की जा सकती है।
- A “kill switch” feature is proposed to instantly disable all digital payment channels.
- एक “किल स्विच” सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे सभी डिजिटल भुगतान चैनल तुरंत बंद किए जा सकें।

Ques: The ‘bob World Lite’ mobile banking app has been launched by which bank in partnership with Jio?

प्रश्न: ‘bob World Lite’ मोबाइल बैंकिंग ऐप किस बैंक ने जियो के साथ मिलकर लॉन्च किया है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda partnered with Reliance Jio to launch “bob World Lite”, a mobile banking app for feature phone users.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर “bob World Lite” मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया, जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए है।
- The app is designed for JioPhone Prima 4G and aims to expand digital banking access in rural and semi-urban areas.

- यह ऐप JioPhone Prima 4G के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग पहुंच बढ़ाना है।
- It enables basic banking services like balance check, fund transfer, and mini statement on feature phones.
- यह फीचर फोन पर बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- The initiative promotes financial inclusion by making banking accessible without smartphones.
- यह पहल बिना स्मार्टफोन के बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Bank – Bank of Baroda
- बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा
- Headquarters – Vadodara, Gujarat
- मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात
- Founded – 1908
- स्थापना – 1908
- Tagline – India's International Bank
- टैगलाइन – इंडिया's इंटरनेशनल बैंक

Ques: Which institution has been designated as the implementing agency for Startup India Fund of Funds 2.0 (FoF 2.0)?

प्रश्न: स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किस संस्था को नामित किया गया है?

- A) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) SEBI / सेबी
- C) NITI Aayog / नीति आयोग
- D) NABARD / नाबार्ड

E) SIDBI / सिडबी

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India launched Startup India Fund of Funds 2.0 (FoF 2.0) to boost the startup ecosystem.
- भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) लॉन्च किया।
- The corpus of the fund is ₹10,000 crore.
- इस फंड का कोष ₹10,000 करोड़ है।
- Small Industries Development Bank of India has been designated as the implementing agency.
- स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
- The scheme builds on the earlier Fund of Funds for Startups (FFS 1.0) launched in 2016.
- यह योजना 2016 में शुरू किए गए फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS 1.0) पर आधारित है।
- Investments will be routed through SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs).
- निवेश SEBI-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के माध्यम से किया जाएगा।
- These AIFs will further invest in startups.
- ये AIFs आगे स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे।
- The scheme focuses on deep-tech, early-stage startups, and technology-driven manufacturing.
- यह योजना डीप-टेक, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स और तकनीक-आधारित विनिर्माण पर केंद्रित है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SIDBI Established – 1990
- SIDBI स्थापना – 1990
- Headquarters – Lucknow
- मुख्यालय – लखनऊ
- Startup India Initiative – Launched in 2016
- स्टार्टअप इंडिया पहल – 2016 में शुरू हुई

Ques: The World Bank approved a \$225 million loan for which state's highway modernisation project?

प्रश्न: विश्व बैंक ने 225 मिलियन डॉलर का ऋण किस राज्य के हाईवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए स्वीकृत किया है?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Maharashtra / महाराष्ट्र
- C) Rajasthan / राजस्थान
- D) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
- E) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- World Bank has approved a \$225 million loan for Rajasthan.
- World Bank ने राजस्थान के लिए 225 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- The loan is meant for the Rajasthan Highway Modernisation Project.
- यह ऋण राजस्थान हाईवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए है।
- The project aims to improve road connectivity and infrastructure in the state.
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- It is expected to benefit more than 3 million people.
- इससे 30 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

- The initiative will boost economic activities and create employment opportunities.
- यह पहल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी।
- Key sectors such as mining, tourism, and logistics will benefit from this project.
- इस परियोजना से खनन, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Organisation – World Bank
- संगठन – विश्व बैंक
- Established – 1944
- स्थापना – 1944
- Headquarters – Washington, D.C., USA
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
- Members – 189 countries
- सदस्य – 189 देश
- Purpose – Provides loans and financial assistance for development projects
- उद्देश्य – विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना

Ques: What is the key directive of RBI's new guidelines on cross-border inward remittances?

प्रश्न: RBI के नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Delay payments for verification / सत्यापन के लिए भुगतान में देरी
- B) Credit payments next week / भुगतान अगले सप्ताह जमा करना
- C) Same-day credit during forex market hours / फॉरेक्स समय में उसी दिन भुगतान जमा करना
- D) Stop inward remittances / इनवर्ड रेमिटेंस रोकना
- E) Limit foreign transactions / विदेशी लेनदेन सीमित करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) has issued new guidelines to speed up cross-border inward remittances.
- Reserve Bank of India (RBI) ने क्रॉस-बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंस को तेज करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- Banks are required to credit remittances received during forex market hours on the same business day.
- बैंकों को निर्देश दिया गया है कि फॉरेक्स मार्केट समय में प्राप्त राशि को उसी कार्यदिवस में खाते में जमा किया जाए।
- Banks must reconcile and confirm nostro accounts in near real-time (within 30 minutes).
- बैंकों को नॉस्ट्रो अकाउंट का 30 मिनट के भीतर रियल-टाइम मिलान करना होगा।
- Customers must be informed immediately upon receiving payment messages.
- पेमेंट संदेश प्राप्त होते ही ग्राहकों को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।
- Payments received after business hours will be credited on the next working day.
- बिजनेस आवर्स के बाद प्राप्त भुगतान अगले कार्यदिवस में जमा होंगे।
- Banks have been given 6 months to implement these guidelines.
- इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए बैंकों को 6 महीने का समय दिया गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी: Genius

- Organisation – Reserve Bank of India (RBI)
- संगठन – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- Established – 1935
- स्थापना – 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Act – FEMA (Foreign Exchange Management Act), 1999

- अधिनियम – फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम), 1999

Ques: Why did the Reserve Bank of India return the application of Ujjivan Small Finance Bank to become a universal bank?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक बनने के आवेदन को क्यों वापस किया?

- A) Insufficient capital / अपर्याप्त पूंजी
- B) Regulatory violations / नियामकीय उल्लंघन
- C) Lack of diversified loan portfolio / लोन पोर्टफोलियो में विविधता की कमी
- D) Merger issues / विलय संबंधी समस्याएं
- E) Low profitability / कम लाभप्रदता

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India returned the application of Ujjivan Small Finance Bank to convert into a Universal Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के आवेदन को वापस कर दिया।
- The main reason was the lack of sufficient diversification in its loan portfolio.
- मुख्य कारण इसके लोन पोर्टफोलियो में पर्याप्त विविधता की कमी थी।
- RBI acknowledged that the bank has made progress in diversification but needs further improvement.
- RBI ने माना कि बैंक ने विविधीकरण की दिशा में प्रगति की है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है।
- The bank has been advised to strengthen its portfolio and reapply later.
- बैंक को अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर बाद में पुनः आवेदन करने की सलाह दी गई है।

- Ujjivan SFB had applied for conversion into a universal bank in February 2025.
- उज्जीवन SFB ने फरवरी 2025 में यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आवेदन किया था।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
- नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- Bank – Ujjivan Small Finance Bank
- बैंक – उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
- Application – Universal Bank Conversion
- आवेदन – यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन
- Reason for Return – Lack of loan diversification
- वापस करने का कारण – लोन पोर्टफोलियो में विविधता की कमी
- Application Year – February 2025
- आवेदन वर्ष – फरवरी 2025

Eligibility Criteria (SFB → Universal Bank) | पात्रता मानदंड:

- Minimum 5 years of satisfactory performance with scheduled status
- कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन (Scheduled status के साथ)
- Shares must be listed on a recognised stock exchange
- शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए
- Minimum Net Worth – ₹1,000 crore (audited)
- न्यूनतम नेट वर्थ – ₹1,000 करोड़ (ऑडिटेड)
- Must meet CRAR norms
- CRAR मानदंड पूरे होने चाहिए
- Net profit in last 2 financial years
- पिछले 2 वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए
- Asset Quality: GNPA ≤ 3%, NNPA ≤ 1%
- एसेट क्वालिटी: GNPA ≤ 3%, NNPA ≤ 1%

Ques: K. Satyanarayana Raju has been appointed as the MD & CEO of which organisation?

प्रश्न: के. सत्यनारायण राजू को किस संगठन का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है?

- A) NPCI / एनपीसीआई
- B) IDPIC / आईडीपीआईसी
- C) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
- D) SIDBI / सिडबी
- E) NABARD / नाबाई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- K Satyanarayana Raju has been appointed as the Managing Director and CEO of Indian Digital Payment Intelligence Corporation.
- के. सत्यनारायण राजू को इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC) का MD और CEO नियुक्त किया गया है।
- He previously served as the MD & CEO of Canara Bank.
- वे पहले केनरा बैंक के MD और CEO रह चुके हैं।
- IDPIC is an AI-driven platform aimed at detecting and preventing real-time digital payment fraud.
- IDPIC एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य रियल-टाइम डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकना है।
- It was incorporated in October 2025 as a Section 8 (not-for-profit) company.
- इसे अक्टूबर 2025 में धारा 8 (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया।
- The platform has been approved by the Reserve Bank of India.
- इस प्लेटफॉर्म को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिली है।
- It is promoted by State Bank of India (50% stake with ₹100 crore investment) and Bank of Baroda.
- इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (50% हिस्सेदारी, ₹100 करोड़ निवेश) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रमोट किया गया है।

Ques: How many transactions were processed by UPI in 2025?

प्रश्न: 2025 में UPI द्वारा कितने लेनदेन प्रोसेस किए गए?

- A) 150 billion / 150 बिलियन
- B) 180 billion / 180 बिलियन
- C) 200 billion / 200 बिलियन
- D) 228.5 billion / 228.5 बिलियन
- E) 250 billion / 250 बिलियन

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Unified Payments Interface processed 228.5 billion transactions in 2025.
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 2025 में 228.5 बिलियन लेनदेन प्रोसेस किए।
- This marks a 33% year-on-year growth compared to 2024.
- यह 2024 की तुलना में 33% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
- The data was reported by Worldline.
- यह आंकड़े वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट में सामने आए हैं।
- UPI continues to be the backbone of India's digital payment ecosystem.
- UPI भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बना हुआ है।
- The growth reflects increasing adoption of digital payments across urban and rural areas.
- यह वृद्धि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को दर्शाती है।

Ques: LIC has announced a bonus issue in which ratio?

प्रश्न: LIC ने किस अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है?

- A) 1:2
- B) 2:1

- C) 1:1
- D) 3:1
- E) 1:3

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Life Insurance Corporation of India (LIC) has approved its first-ever 1:1 bonus issue since listing.
 - भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लिस्टिंग के बाद पहली बार 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है।
 - Shareholders will receive one free share for every one share held.
 - शेयरधारकों को प्रत्येक एक शेयर पर एक अतिरिक्त मुफ्त शेयर मिलेगा।
 - After the bonus issue, LIC's paid-up equity share capital will double to ₹12,649.99 crore.
 - बोनस जारी होने के बाद LIC की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹12,649.99 करोड़ हो जाएगी।
 - LIC's authorised share capital is ₹25,000 crore, while current paid-up capital is ₹6,324.99 crore.
 - LIC की अधिकृत शेयर पूंजी ₹25,000 करोड़ है, जबकि वर्तमान चुकता पूंजी ₹6,324.99 करोड़ है।
 - The move aims to reward investors and improve liquidity and market participation.
 - इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को पुरस्कृत करना और बाजार में तरलता व भागीदारी बढ़ाना है।
 - LIC reported reserves & surplus of ₹146,440.58 crore and PAT of ₹33,998 crore (Dec 2025 period).
 - LIC ने दिसंबर 2025 तक ₹146,440.58 करोड़ का रिजर्व व सरप्लस और ₹33,998 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
-

Ques: The World Bank, along with the Asian Development Bank (ADB), has committed how much total amount for Amaravati Capital Phase-I development?

प्रश्न: अमरावती कैपिटल फेज-1 के विकास के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कुल कितनी राशि देने का वादा किया है?

- A) USD 800 million / 800 मिलियन डॉलर
- B) USD 1,200 million / 1,200 मिलियन डॉलर
- C) USD 1,600 million / 1,600 मिलियन डॉलर
- D) USD 2,000 million / 2,000 मिलियन डॉलर
- E) USD 3,000 million / 3,000 मिलियन डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- World Bank and Asian Development Bank have jointly committed USD 1,600 million for Amaravati Capital Phase-I.
- विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मिलकर अमरावती कैपिटल फेज-1 के लिए USD 1,600 मिलियन देने का वादा किया है।
- Each institution has committed USD 800 million.
- दोनों संस्थानों ने USD 800-800 मिलियन देने की प्रतिबद्धता जताई है।
- So far, the World Bank has released USD 340 million.
- अब तक विश्व बैंक USD 340 मिलियन जारी कर चुका है।
- Andhra Pradesh is expected to receive another USD 150 million soon.
- आंध्र प्रदेश को जल्द ही USD 150 मिलियन और मिलने की संभावना है।
- The loan carries an interest rate of about 8–8.5% with a 6-year grace period and 29-year maturity.
- इस ऋण पर लगभग 8–8.5% ब्याज दर है, जिसमें 6 वर्ष की ग्रेस अवधि और 29 वर्ष की परिपक्वता अवधि है।
- Repayment will begin from 15 June 2031.
- ऋण की अदायगी 15 जून 2031 से शुरू होगी।
- The Government of India has also committed ₹15,000 crore, with ₹1,400

crore to be funded by the Centre.

- भारत सरकार ने ₹15,000 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें से ₹1,400 करोड़ केंद्र द्वारा दिया जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- World Bank – Established in 1944, HQ: Washington, D.C.
- विश्व बैंक – स्थापना 1944, मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी.
- ADB – Established in 1966, HQ: Manila, Philippines
- ADB – स्थापना 1966, मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
- Amaravati – Planned capital of Andhra Pradesh
- अमरावती – आंध्र प्रदेश की नियोजित राजधानी

Ques: The Reserve Bank of India imposed a penalty on Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd for non-compliance with which norms?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किस नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया?

- A) Basel Norms / बेसल मानदंड
- B) KYC Norms / केवाईसी मानदंड
- C) CRR Requirements / सीआरआर आवश्यकताएं
- D) Priority Sector Lending / प्राथमिक क्षेत्र ऋण
- E) NPA Guidelines / एनपीए दिशानिर्देश

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹7.5 lakh on Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹7.5 लाख

का जुर्माना लगाया।

- The penalty was for non-compliance with Know Your Customer norms.
- यह जुर्माना KYC (Know Your Customer) नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया।
- RBI found that the bank failed to conduct periodic review of customer risk categorisation.
- RBI ने पाया कि बैंक ने ग्राहकों की जोखिम श्रेणी का समय-समय पर पुनरावलोकन नहीं किया।
- As per KYC guidelines, such reviews must be done at least once every six months.
- KYC दिशानिर्देशों के अनुसार यह समीक्षा हर छह महीने में कम से कम एक बार करनी आवश्यक है।
- KYC norms help prevent money laundering and financial fraud.
- KYC नियम मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करते हैं।

Ques: K.V.R. Murty has been appointed as Whole-Time Member of which organization?

प्रश्न: के.वी.आर. मूर्ति को किस संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है?

- A) RBI / आरबीआई
- B) SEBI / सेबी
- C) IRDAI / इरडाई
- D) NABARD / नाबार्ड
- E) PFRDA / पीएफआरडीए

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- K V R Murty has assumed charge as a Whole-Time Member of the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- के. वी. आर. मूर्ति ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के

पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है।

- With this appointment, SEBI now has four whole-time members, filling all sanctioned positions.
- इस नियुक्ति के साथ SEBI में अब चार पूर्णकालिक सदस्य हो गए हैं, जिससे सभी स्वीकृत पद भर गए हैं।
- Earlier, he served as Additional Controller General of Defence Accounts in the Ministry of Defence.
- इससे पहले वे रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त नियंत्रक जनरल (डिफेंस अकाउंट्स) के रूप में कार्यरत थे।
- He has held key roles like Financial Advisor to DRDO and Indian Air Force.
- उन्होंने DRDO और भारतीय वायु सेना के वित्तीय सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
- He also served as Joint Secretary in the Ministry of Corporate Affairs.
- वे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं।
- He played an important role in policy formulation, e-governance initiatives, and corporate law administration.
- उन्होंने नीति निर्माण, ई-गवर्नेंस पहल और कॉर्पोरेट कानून प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Established – 1988 (Statutory powers in 1992)
- स्थापना – 1988 (1992 में वैधानिक शक्तियाँ)
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडे

Ques: The 'Pocket Money' feature introduced by Google Pay operates on which system?

प्रश्न: Google Pay द्वारा शुरू किया गया 'Pocket Money' फीचर किस प्रणाली पर आधारित है?

- A) IMPS / आईएमपीएस
- B) NEFT / एनईएफटी
- C) Wallet System / वॉलेट सिस्टम
- D) RTGS / आरटीजीएस
- E) UPI Circle / यूपीआई सर्कल

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Google Pay (GPay) introduced a new feature called 'Pocket Money'.
- Google Pay (GPay) ने 'Pocket Money' नामक एक नया फीचर लॉन्च किया।
- This feature works on the UPI Circle system.
- यह फीचर UPI सर्कल सिस्टम पर आधारित है।
- It allows children or family members to make UPI payments without having their own bank accounts.
- यह बच्चों या परिवार के सदस्यों को बिना अपने बैंक खाते के UPI भुगतान करने की सुविधा देता है।

- There are two types of users:
 - Primary User (e.g., parents) with a linked bank account
 - Secondary User (e.g., children, family members, staff)
- इसमें दो प्रकार के यूज़र होते हैं:
 - प्राइमरी यूज़र (जैसे माता-पिता) जिनका बैंक खाता लिंक होता है
 - सेकेंडरी यूज़र (जैसे बच्चे, परिवार के सदस्य, स्टाफ)

- Secondary users can make payments using the primary user's bank account.
- सेकेंडरी यूज़र, प्राइमरी यूज़र के बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- This feature improves financial inclusion and ease of digital payments.
- यह फीचर डिजिटल भुगतान को आसान बनाता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।

Ques: The FIFA World Cup 2026 Pixel Credit Card launched by Visa and HDFC Bank is a variant of which existing card?

प्रश्न: Visa और HDFC Bank द्वारा लॉन्च किया गया FIFA World Cup 2026 Pixel Credit Card किस मौजूदा कार्ड का वेरिएंट है?

- A) Regalia Credit Card / रेगालिया क्रेडिट कार्ड
- B) Millennia Credit Card / मिलेनिया क्रेडिट कार्ड
- C) Pixel Play Credit Card / पिक्सेल प्ले क्रेडिट कार्ड
- D) Diners Club Card / डाइनर्स क्लब कार्ड
- E) Freedom Credit Card / फ्रीडम क्रेडिट कार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Visa and HDFC Bank launched a limited-edition FIFA World Cup 2026 Pixel Credit Card.
- Visa और HDFC Bank ने FIFA World Cup 2026 Pixel Credit Card लॉन्च किया।
- The card is a special variant of HDFC Bank's Pixel Play digital credit card.
- यह HDFC Bank के Pixel Play डिजिटल क्रेडिट कार्ड का विशेष वेरिएंट है।
- It features a FIFA-themed design to attract football fans.
- इसमें FIFA थीम आधारित डिजाइन दिया गया है।
- The launch is accompanied by a nationwide 'Spend & Win' campaign.
- इसके साथ 'Spend & Win' अभियान भी चलाया गया है।
- The card is available to both existing and new customers via the PayZapp app and the bank's website.
- यह कार्ड PayZapp ऐप और बैंक की वेबसाइट के माध्यम से मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- HDFC Bank – Founded in 1994, HQ: Mumbai
- HDFC बैंक – स्थापना 1994, मुख्यालय: मुंबई

- Visa – Global payments technology company
 - Visa – वैश्विक भुगतान तकनीकी कंपनी
 - Credit Card – Allows borrowing within a limit
 - क्रेडिट कार्ड – एक निश्चित सीमा तक उधार की सुविधा
-

Ques: What growth rate has the IMF projected for India for FY27?

प्रश्न: IMF ने FY27 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है?

- A) 5.5%
- B) 6.0%
- C) 6.5%
- D) 6.9%
- E) 7.2%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- International Monetary Fund (IMF) has raised India's GDP growth forecast for FY27 to 6.5%.
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है।
- The revision reflects India's economic resilience despite global challenges.
- यह संशोधन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।
- IMF has projected inflation at 4.7%, slightly higher than Reserve Bank of India (RBI)'s estimate of 4.6%.
- IMF ने महंगाई 4.7% अनुमानित की है, जो RBI के 4.6% अनुमान से थोड़ी अधिक है।
- India's current account deficit is expected to remain around 2% of GDP.
- भारत का चालू खाता घाटा लगभग GDP का 2% रहने की संभावना है।
- Other institutions have also revised forecasts upward:
 - World Bank: 6.6%
 - Asian Development Bank (ADB): 6.9%
 - RBI: 6.9%

- अन्य संस्थानों ने भी अनुमान बढ़ाए हैं।
- Growth is expected to remain steady at 6.5% in 2027–28 as well.
- 2027–28 में भी विकास दर 6.5% रहने की संभावना है।

Ques: CSB Bank Limited launched which retail product to strengthen its retail banking portfolio?

प्रश्न: CSB बैंक लिमिटेड ने अपने रिटेल बैंकिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए कौन सा उत्पाद लॉन्च किया?

- A) Smart Loan Scheme / स्मार्ट लोन योजना
- B) Smart Invest Plan / स्मार्ट इन्वेस्ट प्लान
- C) Digital Gold Account / डिजिटल गोल्ड अकाउंट
- D) Smart Save Account / स्मार्ट सेव अकाउंट
- E) Easy Credit Card / ईजी क्रेडिट कार्ड

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- CSB Bank Limited launched its first dedicated retail product 'SMART SAVE ACCOUNT'.
- CSB बैंक लिमिटेड ने अपना पहला समर्पित रिटेल उत्पाद 'SMART SAVE ACCOUNT' लॉन्च किया।
- The initiative aims to strengthen its retail banking portfolio.
- इस पहल का उद्देश्य रिटेल बैंकिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करना है।
- The account is available in three variants: Savings, Current, and Non-Resident Ordinary (NRO).
- यह खाता तीन प्रकारों में उपलब्ध है: सेविंग्स, करंट और नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (NRO)।
- It caters to a wide range of customers including individuals and NRIs.
- यह विभिन्न ग्राहकों जैसे व्यक्तियों और एनआरआई को ध्यान में रखकर बनाया गया

है।

- The new savings account features an auto-sweep facility, transferring additional funds into Fixed Deposits (FDs)
- नए बचत खाते में ऑटो-स्वीप सुविधा है, जिसके तहत अतिरिक्त धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में स्थानांतरित हो जाती है।
- It offers maximum 7% interest on 'Sweep-in FDs' over a 13-month tenure.
- यह 13 महीने की अवधि के लिए 'स्वीप-इन एफडी' पर अधिकतम 7% ब्याज प्रदान करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- CSB Bank Founded – 26 November 1920
- CSB बैंक स्थापना – 26 नवंबर 1920
- Headquarters – Thrissur, Kerala
- मुख्यालय – त्रिशूर, केरल

Ques: What was India's retail inflation (CPI) rate in March 2026 as per NSO data?

प्रश्न: NSO के अनुसार मार्च 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) दर क्या थी?

- A) 2.75%
- B) 3.2%
- C) 3.4%
- D) 3.8%
- E) 4.0%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's retail inflation (CPI) rose marginally to 3.4% in March 2026.
- मार्च 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) बढ़कर 3.4% हो गई।
- It was 3.21% in February 2026.

- फरवरी 2026 में यह 3.21% थी।
- The data is released by the National Statistics Office.
- यह आंकड़े नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी किए जाते हैं।
- The inflation figures are based on a new base year 2023–24.
- मुद्रास्फीति के आंकड़े 2023–24 को आधार वर्ष मानकर जारी किए गए हैं।

Recent CPI Inflation | हाल की CPI मुद्रास्फीति:

- January 2026 – 2.75%
- जनवरी 2026 – 2.75%
- February 2026 – 3.2%
- फरवरी 2026 – 3.2%
- March 2026 – 3.4%
- मार्च 2026 – 3.4%

Ques: SEBI signed MoU with which department to curb fraud?

प्रश्न: SEBI ने धोखाधड़ी रोकने के लिए किस विभाग के साथ MoU किया?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) RBI / आरबीआई
- C) Department of Telecommunications / दूरसंचार विभाग
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) Ministry of IT / आईटी मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) signed an MoU with the Department of Telecommunications (DoT).

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने Department of Telecommunications (DoT) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The aim is to curb securities market fraud and telecom-linked financial crimes.
- इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट फ्रॉड और टेलीकॉम आधारित वित्तीय अपराधों को रोकना है।
- It enables regular data sharing via Digital Intelligence Platform (DIP) for real-time monitoring.
- इसके तहत Digital Intelligence Platform (DIP) के माध्यम से रियल-टाइम डेटा शेयरिंग संभव होगी।
- This collaboration strengthens cybersecurity, fraud detection, and regulatory oversight.
- यह सहयोग साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की पहचान और नियामक निगरानी को मजबूत करता है।
- It helps in better protection of investors and financial systems.
- इससे निवेशकों और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SEBI – Established: 1988 (Statutory: 1992), HQ: Mumbai
- सेबी – स्थापना: 1988 (वैधानिक: 1992), मुख्यालय: मुंबई
- DoT – Under Ministry of Communications
- दूरसंचार विभाग – संचार मंत्रालय के अंतर्गत
- DIP – Digital Intelligence Platform
- डीआईपी – डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म
- Purpose – Fraud Prevention & Cybersecurity
- उद्देश्य – धोखाधड़ी रोकथाम और साइबर सुरक्षा

Ques: What was India's Wholesale Price Index (WPI)-based inflation rate in March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी?

- A) 2.5%
- B) 3.2%
- C) 3.5%
- D) 3.9%
- E) 4.2%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- India's wholesale inflation rose to 3.9% in March 2026.
- मार्च 2026 में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 3.9% हो गई।
- It is a three-month peak as per data released by the Ministry of Commerce and Industry.
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तीन महीने का उच्चतम स्तर है।
- WPI measures price changes in the wholesale market.
- WPI थोक बाजार में कीमतों में बदलाव को मापता है।
- The WPI-based inflation data is compiled by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade.
- WPI आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े DPIIT द्वारा तैयार किए जाते हैं।
- Rising WPI indicates increasing cost pressures at the producer level.
- WPI में वृद्धि उत्पादक स्तर पर लागत बढ़ने का संकेत देती है।

Ques: As per RBI's Master Direction on Counterfeit Notes, what action must a bank take if 5 or more counterfeit notes are detected in a single transaction?

प्रश्न: RBI के नकली नोटों पर मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, एक लेनदेन में 5 या अधिक नकली नोट मिलने पर बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए?

- A) Send monthly report to RBI / RBI को मासिक रिपोर्ट भेजें
- B) Return notes to tenderer / नोट देने वाले को वापस करें

C) Destroy the notes immediately / नोट तुरंत नष्ट करें

D) File FIR and forward notes immediately to police / तुरंत FIR दर्ज करें और नोट पुलिस को भेजें

E) Send consolidated report at month end / महीने के अंत में समेकित रिपोर्ट भेजें

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) issued a Master Direction on Counterfeit Notes under Section 35A and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत नकली नोटों पर मास्टर डायरेक्शन जारी किया।
- The objective is to unify guidelines on detection, reporting, and monitoring of counterfeit notes by banks.
- इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा नकली नोटों की पहचान, रिपोर्टिंग और निगरानी के दिशानिर्देशों को एकीकृत करना है।
- All ₹100 and above banknotes must be machine-verified before re-circulation; manual checking alone is not allowed.
- ₹100 और उससे अधिक के नोटों को पुनः संचलन से पहले मशीन से सत्यापित करना अनिवार्य है; केवल मैनुअल जांच पर्याप्त नहीं है।
- Detected counterfeit notes must be stamped "COUNTERFEIT BANKNOTE", impounded, and a receipt must be issued to the tenderer.
- पकड़े गए नकली नोटों पर "COUNTERFEIT BANKNOTE" की मुहर लगाकर जब्त किया जाए और देने वाले को रसीद दी जाए।
- These notes cannot be returned to the tenderer or destroyed under any circumstances.
- इन नोटों को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है।
- For 1–4 counterfeit notes in a transaction: a consolidated monthly report is sent to police at month end.
- एक लेनदेन में 1–4 नकली नोट मिलने पर महीने के अंत में पुलिस को समेकित रिपोर्ट भेजी जाती है।

- For 5 or more counterfeit notes: banks must immediately inform police and file an FIR.
- एक लेनदेन में 5 या अधिक नकली नोट मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना देकर FIR दर्ज करना अनिवार्य है।
- Banks must also establish a Forged Note Vigilance Cell at Head Office for monitoring.
- बैंकों को अपने मुख्यालय में जाली नोट सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Direction – RBI Master Direction on Counterfeit Notes
- दिशा-निर्देश – RBI नकली नोट मास्टर डायरेक्शन
- Issued By – Reserve Bank of India (RBI)
- जारीकर्ता – भारतीय रिज़र्व बैंक
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Legal Basis – Section 35A & 56, Banking Regulation Act, 1949
- कानूनी आधार – धारा 35A एवं 56, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- Issued In – April 2026
- जारी वर्ष – अप्रैल 2026
- Machine Verification – Mandatory for ₹100+ notes
- मशीन सत्यापन – ₹100+ नोटों के लिए अनिवार्य
- Action on Detection – Stamp + Impound + Receipt
- कार्रवाई – मुहर + जब्ती + रसीद
- Stamp Used – “COUNTERFEIT BANKNOTE”
- उपयोग की जाने वाली मुहर – “COUNTERFEIT BANKNOTE”

Ques: Under Part A of PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY), what is the maximum incentive amount provided to a first-time employee and after how many months is it payable?

प्रश्न: PM विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के Part A के तहत पहली बार

कार्यरत कर्मचारी को अधिकतम कितना प्रोत्साहन दिया जाता है और यह कितने महीनों के बाद देय है?

- A) ₹10,000 — after 3 and 6 months / ₹10,000 — 3 और 6 महीने बाद
- B) ₹15,000 — after 6 and 12 months / ₹15,000 — 6 और 12 महीने बाद
- C) ₹20,000 — after 6 and 12 months / ₹20,000 — 6 और 12 महीने बाद
- D) ₹15,000 — after 12 and 24 months / ₹15,000 — 12 और 24 महीने बाद
- E) ₹3,000 per month — for 2 years / ₹3,000 प्रति माह — 2 वर्ष तक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) was launched in August 2025 with an outlay of ₹99,446 crore.
- PM विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) अगस्त 2025 में ₹99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई।
- The scheme aims to generate 35 million formal jobs between August 2025 and July 2027.
- इस योजना का लक्ष्य अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच 35 मिलियन औपचारिक रोजगार सृजित करना है।
- In the first 6 months, only 4.41 lakh employees benefited, which is just 10% of the required pace.
- पहले 6 महीनों में केवल 4.41 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला, जो लक्ष्य की अपेक्षित गति का मात्र 10% है।
- The government disbursed ₹465 crore to around 4.41 lakh employees across 18,000 establishments.
- सरकार ने 18,000 प्रतिष्ठानों में लगभग 4.41 लाख कर्मचारियों को ₹465 करोड़ वितरित किए।
- Part A (Employee Benefit): Provides up to ₹15,000 (one-month EPF wage) in two instalments after 6 and 12 months of continuous service for employees earning up to ₹1 lakh.
- Part A (कर्मचारी लाभ): ₹1 लाख तक वेतन वाले कर्मचारियों को 6 और 12 महीने की

सेवा के बाद दो किस्तों में ₹15,000 तक (एक महीने की EPF मजदूरी) दी जाती है।

- Part B (Employer Incentive): Provides up to ₹3,000 per month per additional employee for 2 years (4 years for manufacturing sector).
- Part B (नियोक्ता प्रोत्साहन): प्रत्येक नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रति माह तक 2 वर्षों के लिए (विनिर्माण क्षेत्र में 4 वर्षों तक) दिया जाता है।
- The scheme is administered by EPFO (Employees' Provident Fund Organisation).
- यह योजना EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा संचालित की जाती है।
- Slow progress is partly due to geopolitical tensions like the West Asia conflict, affecting hiring.
- धीमी प्रगति का एक कारण पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनाव हैं, जिससे भर्ती प्रभावित हुई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Scheme – PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY)
- योजना – PM विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)
- Type – Employment Linked Incentive (ELI) Scheme
- प्रकार – रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना
- Launch Date – August 1, 2025
- लॉन्च तिथि – 1 अगस्त 2025
- Duration – August 2025 to July 2027
- अवधि – अगस्त 2025 से जुलाई 2027
- Target – 35 million jobs
- लक्ष्य – 35 मिलियन नौकरियां
- First-time Beneficiary Target – 19.2 million
- पहली बार लाभार्थी लक्ष्य – 19.2 मिलियन
- Administered By – EPFO
- संचालित – EPFO
- Amount Disbursed (6 months) – ₹465 crore
- वितरित राशि (6 महीने) – ₹465 करोड़
- Beneficiaries – 4.41 lakh employees
- लाभार्थी – 4.41 लाख कर्मचारी
- Establishments Covered – 18,000

- शामिल प्रतिष्ठान – 18,000

Ques: As per RBI's Master Direction on Exchange of Notes, within how many days must a bank credit the value of soiled notes presented in bulk (more than 20 pieces)?

प्रश्न: RBI के नोट विनिमय मास्टर डायरेक्शन के अनुसार, बल्क में जमा किए गए मैले नोटों (20 से अधिक) का मूल्य बैंक को कितने दिनों में जमा करना होगा?

- A) 3 days / 3 दिन
- B) 7 days / 7 दिन
- C) 15 days / 15 दिन
- D) 30 days / 30 दिन
- E) 45 days / 45 दिन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) issued the Master Direction on Exchange of Notes & Coins in April 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2026 में नोट और सिक्कों के विनिमय पर मास्टर डायरेक्शन जारी किया।
- The objective is to unify all instructions related to exchange of currency and improve public convenience.
- इसका उद्देश्य मुद्रा विनिमय से जुड़े सभी निर्देशों को एकीकृत करना और जनता की सुविधा बढ़ाना है।
- All bank branches must provide exchange facilities to everyone, including non-customers.
- सभी बैंक शाखाओं को गैर-ग्राहकों सहित सभी को नोट बदलने की सुविधा देनी होगी।
- Banks cannot refuse coins or small denomination notes as they are legal tender.

- बैंक सिक्के या छोटे मूल्यवर्ग के नोट लेने से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये वैध मुद्रा हैं।

- Soiled Notes (मैले नोट):

- Up to 20 notes or ₹5,000/day → exchanged over the counter free of charge
- More than 20 notes or above ₹5,000 → accepted with receipt and credited within 7 days

- मैले नोट:

- 20 नोट या ₹5,000/दिन तक → काउंटर पर मुफ्त बदले जाएंगे

- 20 से अधिक या ₹5,000 से ऊपर → रसीद के साथ स्वीकार, 7 दिनों में क्रेडिट

- Mutilated Notes (क्षतिग्रस्त नोट):

- Up to 10 notes → adjudicated and paid at counter

- Above 10 notes or ₹5,000 → credited within 30 days

- क्षतिग्रस्त नोट:

- 10 नोट तक → काउंटर पर जांच कर भुगतान

- 10 से अधिक या ₹5,000 → 30 दिनों में क्रेडिट

- Small Finance Banks (up to 2 years old) and Payment Banks are exempt — exchange is optional for them.

- छोटे वित्त बैंक (2 वर्ष तक) और पेमेंट बैंक के लिए यह सुविधा वैकल्पिक है।

- Key Rule: Soiled notes bulk → 7 days | Mutilated notes bulk → 30 days

- मुख्य नियम: मैले नोट (बल्क) → 7 दिन | क्षतिग्रस्त नोट (बल्क) → 30 दिन

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Direction – RBI Master Direction on Exchange of Notes & Coins

- दिशा-निर्देश – RBI नोट व सिक्का विनिमय मास्टर डायरेक्शन

- Issued By – RBI

- जारीकर्ता – RBI

- Governor – Sanjay Malhotra

- गवर्नर – संजय मल्होत्रा

- Headquarters – Mumbai

- मुख्यालय – मुंबई

- Effective – April 2026

- प्रभावी – अप्रैल 2026

- Legal Authority – Section 35A & 56, Banking Regulation Act, 1949

- कानूनी आधार – धारा 35A एवं 56, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- Soiled Note – Dirty or worn note
- मैले नोट – गंदा या घिसा हुआ नोट
- Mutilated Note – Torn or missing portion
- क्षतिग्रस्त नोट – फटा हुआ या हिस्सा गायब
- Coins Legal Tender – 50 paise, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20
- सिक्के वैध मुद्रा – 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20

